भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2007
दिनांक 11 दिसंबर 2025

वारंगल में सीएनजी स्टेशन का विकास और विस्तार

†2007. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वारंगल में सीएनजी स्टेशन नेटवर्क के विकास और विस्तार में कितनी प्रगति हुई है;
(ख) वारंगल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एलपीजी के लिए दी गई सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वारंगल के पास तेल अन्वेषण की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर वारंगल में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना करना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का एक हिस्सा है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा उनके न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्लूपी) के अनुसार किया जाता है। पीएनजीआरबी ने 12/12ए सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के बाद, देश भर में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए संपूर्ण मुख्य भूमि क्षेत्र को शामिल करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु कंपनियों को प्राधिकृत किया है।

वारंगल, जंगांव, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबाबाद, वारंगल शहर और वारंगल ग्राम के जिलों के भौगोलिक क्षेत्र (जीए) का हिस्सा है, जिसे पीएनजीआरबी द्वारा मैसर्स मेघा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को सितंबर, 2018 में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकृत किया गया है। एमडब्लूपी के अनुसार सीजीडी कंपनी ने वर्ष 2028 तक जीए में 12 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की है। दिनांक 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत कंपनी ने जीए में 7 सीएनजी स्टेशनों के आनुपातिक एमडब्लूपी लक्ष्य के सापेक्ष 10 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं।

(ख) देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में शुरू की गई थी। 1 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, वारंगल (तेलंगाना) के 0.42 लाख कनेक्शन सहित देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200 रुपये की निर्धारित राजसहायता (और यथानुपातिक रूप से 5 किलोग्राम कनेक्शन हेतु आनुपातिक) प्रदान करना आरंभ किया। सरकार ने अक्टूबर 2023 में निर्धारित राजसहायता को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपये (और यथानुपातिक रूप से 5 किलोग्राम कनेक्शन हेतु आनुपातिक) किया। सरकार, वित्त वर्ष 2025-26 हेतु देश भर में तेलंगाना के वारंगल जिले के लाभार्थियों सहित पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की 9 रिफिल तक प्रति 14.2 के किलोग्राम सिलेंडर(और यथानुपातिक रूप से 5 किलोग्राम कनेक्शन हेतु आनुपातिक) पर 300 रुपये की निर्धारित राजसहायता प्रदान कर रही है।

(ग) वारंगल तेलंगाना राज्य में स्थित है, जहाँ वर्तमान में कोई सक्रिय ओएएलपी ब्लॉक उपलब्ध नहीं है। हालांकि, ओएएलपी दौर-VI के तहत प्रदान किए गए कुड्डापाह बेसिन में स्थित एक सक्रिय ओएएलपी ब्लॉक सीडी-ओएनएचपी-2020/1 है जो वारंगल से लगभग 350 किमी दूर स्थित है। इस ब्लॉक का प्रचालन ओएनजीसी द्वारा किया जाता है और वर्तमान में यह अन्वेषण के चरण में है।

(घ) तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने तेलंगाना स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति, 2025 अधिसूचित की है। इस नीति के अंतर्गत, ग्रिड-स्तरीय सौर परियोजनाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और स्थानीय निकायों द्वारा विकेन्द्रीकृत जमीनी-सौर संयंत्रों और घर की छत का सौरीकरण, सरकारी शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देकर नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक एकीकरण परिकल्पित है। इस नीति का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित करना भी है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) के तहत, दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार वारंगल जिले में कुल 596 रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी), हरित हाइड्रोजन आदि जैसे विभिन्न नवीकरणीय और जैव ईंधनों के उत्पादन तथा उपयोग के माध्यम से देश भर में एक हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में भी कई और कदम भी उठाए हैं।

*****